THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (e) Govt. of India, in consultation with its concerned Departments have issued an ad-hoc exemption order permitting Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) to import 2 million tonnes of coal for its thermal power stations at concessional import duty of 30% to maintain adequate stock of good quality of coal to ensure uninterrupted generation of power. Award of contract for import of coal is the prerogative of the State concerned.

DESU dues to Various Organisations

2013. SHRI GAYA SINGH:

SHRI MATANG SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of big industrial units and bulk consumers of electricity are in default and a huge amount of arrears against each of them remains to be recovered by DESU;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some consumers have gone to court and their cases are subjudice;

(d) if so, the details, number and amount in each case;

(e) whether DESU has the power to attach properties of defaulters including those who have gone to court; and

(f) if so, what are the reasons for not taking action to attach their properties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त किया जाना

2014 **श्री अजीत जोगी** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया जा रहा है और उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां पर ये परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) :

(क) और (ख) कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल 1651 मिलियन अमरीकी डालर ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

Meter rent being charged by DESU

2015. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that DESU has been issuing provisional electricity bills to consumers without any meter reading; including therein charges for some units of electricity, meter rent and the 2 per cent tax;

(b) whether it is also a fact that when the actual bill in accordance with meter reading is sent it again includes the meter rent already paid in the provisional bill whereas the other two amounts are subtracted; and

(c) if so, what are the reasons that DESU is charging the meter rent twice and what corrective steps are contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. The present rate of Electricity Tax is, however, 5% of the energy bill.

(b) Meter Rent already charged in the provisional bill is not included in the subsequent bill based on meter reading. However, appropriate action is taken by DESU to rectify the bill, if any error on

this account is brought to their notice by the consumer.

(c) Does not arise in view of the reply to part (b) above.

मध्य प्रदेश को विद्युत परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना

2016. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की कतिपय विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के प्रारंभ तथा पूर्ण होने की संभावित तिथियां क्या-क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है:-

क्र०सं०	परियोजना/ राज्य का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1.	पेंच ता० वि०के०/म०प्र०	भारतीय	420.00 (2 × 210) (कोयला)	1567.96	सैंचूरी पावर
2.	महेश्वर एचईपी/म०प्र०	भारतीय	400.00 (10 × 40) (जल विद्युत)	602.54	एस० कुमार्स
3.	कोरबा वैस्ट विस्तार यूनिट 5 एवं 6 ता० वि०के० म०प्र०	भारतीय	420.00 (2 × 220) (कोयला)	977.57	मुकुन्द लि०
4.	भिलाई कैप्टिव ता०वि० के०/म०प्र०	भारतीय/ संयुक्त उपक्रम	500.00	1200.00	एनटीपीसी/सेल
5.	तावा ता०वि०के/म०प्र०	भारतीय	12.00 (जल विद्युत)	20.00	एचईजी लि०

(ग) परियोजना के प्रवर्तक सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों के साथ परियोजना पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। और विभिन्न सांविधिक और गैर सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर रहे हैं। परियोजनाओं को आरम्भ और पूरा होने सम्बन्धी समय सारणी इनके सुनिश्चित होने के बाद ही पता चल सकेगी।